आर.एन.आई. पंजीयन क्र. 39596/82 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)

साप्ताहिक

मालव अँचल

वर्ष 47 अंक 20 (प्रति रविवार) इंदौर, 04 फरवरी से 10 फरवरी 2024 पृष्ठ-8 मूल्य 3 रुपये

परिवारवाद का खामियाजा कांग्रेस ने भुगता-मोदी

एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के चक्कर में दुकान पर ताला लगने की नौबत आ गई

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्पीच पर धन्यवाद भाषण दे रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष, कांग्रेस और परिवारवाद पर तीखे बयान दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ही प्रोडक्ट को कई बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान पर ताला लगने की नौबत आ गई। देश के साथ-साथ कांग्रेस ने भी परिवारवाद का खामियाजा भुगता।

मोदी ने कहा- ये विपक्ष कई दशक तक सत्ता में बैठा था, वैसे ही इस विपक्ष ने कई दशक तक विपक्ष में बैठने का संकल्प लिया है। ईश्वररूपी जनता के आशीर्वाद से ये अगले चुनाव में दर्शक दीर्घा में दिखेंगे। मोदी ने कहा कि अबकी बार 400 पार, ये बात देश ही नहीं खड़गेजी भी बोल रहे हैं। जनता भाजपा को 370 सीटें जरूर देगी।

हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, आइए साथ मिलकर काम करें- हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। मैं सभी राजनीतिक दलों से सभी सदस्यों से अपील करता हूं- देश से बढ़कर कुछ नहीं। कंधे से कंधा मिलाकर हम देश के निर्माण के लिए आगे बढ़ें। मैं आपका साथ मांग रहा हूं। मैं विश्व के अंदर जो अवसर आया है, उसे भुनाने के लिए आपका साथ चाहता हूं। लेकिन आप अगर साथ नहीं दे सकते, आपका हाथ ईट फेंकने के लिए ही है, तो आपको बता दूं कि आपके फेंकी हर ईट पत्थर को विकसित भारत की नींव में लगा दूंगा। ये नामदार है, हम कामदार हैं। कामदारों को नामदारों से सुनना ही पड़ता है। हम सुनते भी रहेंगे और देश को आगे बढ़ाते रहेंगे।

खुलेआम देश में अलग देश की वकालत करने वाले, जोड़ने की बातें छोड़ो तोड़ने की बात करते हैं। इतने टुकड़े करने

के बाद भी आप कितने टुकड़े करना चाहते हैं। इसी सदन में कश्मीर की बात होती थी, चिंता का स्वर निकलता था, आज जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व विकास की चर्चा हो रही है। पर्यटन बढ़ रहा है। जी20 समिट होती है वहां, विश्व सराहना कर रहा है। 370 हटने से कश्मीर खुश है, यह दरार किसने डाली। नेहरू जी का नाम लेने पर उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन कश्मीर की समस्या के मूल में वे ही थे। कश्मीर के लोगों को नेहरू जी की गलतियां की सजा चुकानी पड़ी।

देश सुरक्षा और शांति का एहसास कर रहा- देश सुरक्षा और शांति का एहसास कर रहा है। आतंकवाद नक्सलवाद छोटे दायरे में सिमट गए हैं। भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति पूरे विश्व को इस रास्ते पर चलने को मजबूर कर रही हैं। भारतीय सेनाएं बार्डर से समुद्र तक मजबूती से अपना काम कर रही हैं।

जिसने देश को लूटा है, उसे लौटाना पड़ेगा- जहां संविधान का राज है, जहां लोकतंत्र है, वहां ऐसी बातें लंबी नहीं चल सकती हैं। जांच करना एजेंसियों का काम है, एजेंसियां स्वतंत्र रहती हैं। जज करने का काम न्यायाधीशों का है। वे अपना काम कर रहे हैं। जिसको जितना जुल्म करना है, कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। जिसने देश को लूटा है, उसे लौटाना पड़ेगा। देश को लुटने नहीं दिया जाएगा।

चोरी में जेल जाने पर महिमा मंडन किया जाता है- सभी राजनीतिक दलों को भी सोचने की जरूरत है। आज देश का दुर्भाग्य है पहले क्लास में कोई चोरी करता था तो दस दिन तक किसी को अपना मुंह नहीं दिखाता था। आज जिस पर भ्रष्टाचार सिद्ध हो जाता है। चोरी में जेल हो आता है। उनका महिमा-मंडन किया जा रहा है। आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है।

अब बिचौलियों के लिए गरीबों को लूटना मुश्किल हुआ- अब बिचौलियों के लिए गरीबों को लूटना मुश्किल हो गया है। डायरेक्ट बैनिफिट स्कीम से लोग लूटने से बचे। कांग्रेस के पीएम ने कहा था- एक रुपए भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं। हमने 30 लाख करोड़ भेजे, पूरे पहुंचे। हमने 10 करोड़ फर्जी नाम हटाए। उनकी व्यवस्था ऐसी थी, जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ, उसे विधवा पेंशन जाती थी।

चुनाव आयोग बोला-चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल न करें

रैली से दूर रखें, न गोद में उठाएं और न गाड़ी में बैठाएं

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सोमवार 5 फरवरी को सभी राजनीतिक दलों को सलाह दी है कि चुनाव प्रचार अभियानों में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी रूप में न करें। पार्टियों को भेजी गई एडवाइजरी में चुनाव पैनल ने पार्टियों और उम्मीदवारों से चुनावी प्रक्रिया के दौरान बच्चों से पोस्टर और पर्चे बांटने, नारेबाजी करने को लेकर जीरो टॉलरेंस जाहिर किया है।

आयोग ने कहा कि राजनीतिक नेता और उम्मीदवार प्रचार के दौरान बच्चों को गोद में लेने और गाड़ियों में में न बैठाएं, न उनको रैली में शामिल करें।

बच्चों से कविता-गीत पढ़वाने और भाषण पर भी रोक रहेगी- चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि यह प्रतिबंध कविता, गाने, बोले गए शब्दों, राजनीतिक दल या उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल के अलावा किसी भी तरीके से राजनीतिक अभियान की झलक बनाने के लिए बच्चों के उपयोग पर भी लागू होगा।

हालांकि, किसी बच्चे के माता-पिता या अभिभावक राजनेता के करीबी हैं और वे अपने साथ बच्चे को ले जाते हैं तो इसे दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, बशर्ते वे उनकी पार्टी के चुनाव प्रचार में शामिल न हों। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राजनीतिक दलों से संसदीय चुनावों में लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में की भी अपील की है।

चुनाव में बच्चों के इस्तेमाल पर पोलिंग अफसर होंगे जिम्मेदार- आयोग ने सभी चुनाव अधिकारियों और मशीनरी को निर्देश दिया है कि वे चुनाव से जुड़ें किसी भी काम या गतिविधियों के दौरान बच्चों को शामिल करने से बचें। इसके लिए चाइल्ड लेबर से जुड़े सभी कानूनों का पालन किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। इनके अलावा लोकसभा क्षेत्रों में काम कर रही चुनावी मशीनरी पर भी इन प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर एक्शन लिया जाएगा।

थरूर बोले-बीते 10 साल में बहुत 'मैं-मेरा' सुन लिया, एक दशक में सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात हुई है, अब बदलाव आना चाहिए

जयुपर (एजेंसी)। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने रविवार को पीएम मोदी पर निशाना साधा। थरूर ने कहा कि बीते 10 साल में हमने बहुत सारा 'आई, माय, मायसेल्फ' (मैं और मेरा) सुना है। इन सालों में सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात हुई है। इस 'मैं' का समाधान है ऐसी लीडरशिप तैयार करना जो अपनी बड़ाई न करती हो, बल्कि पूरी विनम्रता के साथ आपकी बात सुनती हो, आपकी बात करती हो, आपकी जरूरतों को समझती हो और उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करती हो। थरूर ने ये बातें रविवार को 17वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कहीं। वे यहां इंद्रजीत रॉय की किताब 'ऑडैशियस होपः हाउ टु सेव डेमोक्रेसी' पर चर्चा में शामिल हुए थे। यहां थरूर ने युवाओं से अपील की कि वे आने वाले लोकसभा चुनावों में अपने वोट का सोच-समझकर इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि आखिर में सिर्फ आपका वोट ही मायने रखता है। आपका भविष्य आपके ही हाथों में है।

लोकतंत्र की हत्या हुई है- सीजेआई चंदचूड़

चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामला, वीडियो देखकर कहा कि ये क्या मजाक हो रहा

नई दिल्ली (एजेंसी)। सीजेआई डीवाई चंदचूड़ ने अदालत में वीडियो देखने के दौरान कहा कि क्या ये बैलेट पेपर है... वीडियो देखकर सीजेआई नाराज हो गए और कहा कि ये लोकतंत्र का मजाक है। लोकतंक्त की हत्या हुई है। दरअसल चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की शुरुवात करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक पेन ड्राइव दी। वकील सिंघवी ने हाईकोर्ट के आदेश का जिक्र कर बताया कि कमिश्नर ने रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त किया है। सिंघवी ने कहा कि हम 20 थे बीजेपी 16 थी। वोटिंग में 36 लोग वोट करते है। ऑफिसर ने 8 लोगों को अयोग्य करार दिया। ये सभी लोग हमारे थे। इसके बाद आंकड़ा 20 घटकर 12 हो जाता है। हाईकोर्ट ने बैलेट को सुरक्षित नहीं रखा। बल्कि 3 हफ्ते के लिए नोटिस जारी किया। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष एक वीडियो दिखाया गया। यह वीडियो मतदान के समय का था। ये वीडियो उस समय का था जब वोट को अयोग्य ठहराया जा रहा था। सीजेआई ने वीडियो देखने के दौरान कहा कि क्या ये बैलेट पेपर है वहां हिस्सा कहा है, जिसमें आप दावा कर रहे है कि ऑफिसर बैलेट पेपर ले कर चले गए। वीडियो देखकर सीजेआई नाराज हो गए और कहा कि ये लोकतंत्र का मजाक है। लोकतंक्त की हत्या हुई है। ये क्या रिटर्निंग ऑफिसर करता है। हम नहीं चाहते की देश में लोकतंत्र की हत्या हो। सीजेआई ने मामले में नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव की पवित्रता बरकरार रखने के लिए चंडीगढ़ मेयर चुनाव की डिटेल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जमा होंगी। इतना ही नहीं सीजेआई ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर कैमरे की तरफ क्यों देख रहा है ये कोई भगौड़ा नहीं है।

संपादकीय

भारतीय राजनीति के महारथी लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न

भारत सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को 97 साल की उम्र में भारत रत्न की उपाधि देने का निर्णय किया है। भारतीय जनता पार्टी के तीसरे ऐसे बड़े नेता हैं। जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई तथा जनसंघ के नाना जी देशमुख को भारत रत्न की उपाधि से पहले ही नवाजा जा चुका है। कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। 12 दिन बाद लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की है। भारत रत्न की सूची में लालकृष्ण आडवाणी का 32 वां नंबर होगा। लालकृष्ण आडवाणी का जन्म कराची में हुआ था। विभाजन के बाद वह भारत आए ,और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य बने। उन्होंने राजनीति में नई-नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया। 1984 में भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। उसके मात्र दो सांसद चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। तब लालकृष्ण आडवाणी ने एक नई भूमिका में आए। उन्होंने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकाली, और पूरे देश की राजनीति को बदलने का काम किया। 1991 में लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ। उसमें भाजपा 120 सीट पर चुनाव जीती।चुनाव के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पेरंबदूर में हत्या हो जाने के बाद, दूसरे चरण के चुनाव में भाजपा को जो सफलता मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल पाई। केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार नरसिम्हा राव के नेतृत्व में बनी। लालकृष्ण आडवाणी कट्टर हिंदुत्व का चेहरा लेकर भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। हिंदुत्व की राह पर चलकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। राम जन्मभूमि मंदिर के आंदोलन में उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय वह अयोध्या की बाबरी मस्जिद में उपस्थित थे। जब यह मामला न्यायालय तक पहुंचा, तो उन्होंने बावरी मस्जिद के विध्वंश की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह कारसेवकों को मस्जिद तोड़ने से रोक रहे थे। राम मंदिर निर्माण को लेकर जो श्रेय उन्हें मिलना चाहिए था,वह उन्हें नहीं मिला। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उन्हें आमंत्रण पत्र श्री राम जन्म निर्माण समिति द्वारा नहीं भेजा गया था। जब इसकी आलोचना शुरू हुई, तब उन्हें निमंत्रण भेजा गया। आमंत्रण के साथ यह भी कहा गया कि उनकी उम्र काफी हो गई है। वह प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में ना आएं। यह लालकृष्ण आडवाणी के लिए सदमा था, जिस राम मंदिर के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया। उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उनसे कहा गया, कि वह ना आएं। रही सही कसर जब भारत सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की। उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी और उनके समर्थक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बड़ा वर्ग, इस बात से नाराज था। लालकृष्ण आडवाणी की उपेक्षा भारत सरकार द्वारा की जा रही है। कुछ माह पश्चात लोकसभा के चुनाव होने हैं। इसको ध्यान में रखते हुए डैमेज कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की। राजनीतिक हल्का में इस बात की चर्चा है, विशेष रूप से भाजपा के अंदर। लालकृष्ण आडवाणी ने अपने पूरे जीवन भर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्होंने दावा नहीं किया। उप प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने एक लोह पुरुष के रूप में अपनी छवि बनाई। गुजरात के गोधरा दंगों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई, मुख्यमंत्री पद से नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते थे। उस समय भी लालकृष्ण आडवाणी, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के बचाव में चट्टान की तरह खड़े हो गए थे। वर्तमान में लालकृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल के सबसे वयोवृद्ध सदस्य हैं। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर सभी क्षेत्रों में स्वागत किया जा रहा है। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह भी है, केंद्र की सत्ता में रहते हुए उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के साथ सद्भाव बनाते हुए भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जिसकी प्रशंसा सभी राजनीतिक दल आज भी करते हैं।

भ्रष्टता निवारण है सशक्त लोकतंत्र का आधार

ललित गर्ग

झारखंड राज्य में जमीन खरीद में गड़बड़ी, अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के कथित पुराने मामलों की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई से झारखंड की सरकार संकट में आ गयी और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ केन्द्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का बुगल बजाय हुए है, जिससे राजनीति में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण का नया सूरज उदित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो दुनिया के सबसे बड़े भारत लोकतंत्र के आदर्श एवं सशक्त होने की बड़ी अपेक्षा है। आजादी के अमृत काल में राजनीति का शुद्धिकरण एवं अपराध मुक्ति ही भारत को सशक्त एवं विकसित राष्ट्र बना सकेगा। हेमंत सोरेन के बाद अब अगला नम्बर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल का है। स्पष्ट है कि अब भ्रष्टाचारियों की नैया पार होने वाली नहीं है। अगर ये लोग सोचते हैं कि ताकतवर होने के कारण कानून उन तक नहीं पहुंच सकता, तो ये मुगालते में हैं। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो उन्हें अपने किए की सजा मिलेगी ही। भ्रष्ट आचरण से करोड़ों-अरबों की संपत्ति लूटने वाले नेतागण शायद नहीं जानते कि केंद्र में ऐसी मजबूत सरकार है, जो भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती। इसीलिए तो जांच एजेंसियों को पूरी छूट मिली हुई है कि वे भ्रष्ट आचरण करने वालों को पकड़ें। दबाव मुक्त केन्द्रीय एजेंसियां अपने काम में जुटी भी हुई हैं, उनकी टांग खिंचने की बजाय उनका हौसला बढ़ाना चाहिए।

इनदिनों गैरभाजपा प्रांतों में भ्रष्टाचार के मामले बड़ी संख्या में उजागर हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल आम आदमी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सतेन्द्र जैन, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एवं पश्चिम बंगाल में उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी जेल की सलाखों के पीछे हैं, इनकी गिरफ्तारी बता रही है कि ममता बनर्जी एवं अरविन्द केजरीवाल भ्रष्टाचार मुक्त शासन के कितने ही दावे क्यों न करें, लेकिन उनके वरिष्ठ मंत्री भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के घेरे में हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों एवं विभिन्न प्रांतों की सरकारों में भ्रष्टाचार की बढ़ती स्थितियां गंभीर चिन्ता का विषय है। ऐसा लगता है आज हम जीवन नहीं, राजनीतिक मजबूरियां जी रहे हैं। राजनीति की सार्थकता एवं साफ-सुथरा उद्देश्य नहीं रहा, स्वार्थपूर्ति का जरिया बन गया है। राजनीतिक दल अच्छे-बुरे, उपयोगी-अनुपयोगी का फर्क नहीं कर पा रहे हैं। मार्गदर्शक यानि नेता शब्द कितना पवित्र व अर्थपूर्ण था पर अब नेता खलनायक बन गया है। नेतृत्व व्यवसायी एवं भ्रष्टाचारी बन गया। आज नेता शब्द एक गाली है। जबकि नेता तो पिता का पर्याय था। उसे पिता का किरदार निभाना चाहिए था। पिता केवल वही नहीं होता जो जन्म का हेतु बनता है अपितु वह भी होता है, जो अनुशासन सिखाता है, ईमानदारी का पाठ पढ़ाता है, विकास की राह दिखाता है। आगे बढ़ने का मार्गदर्शक बनता है।

भ्रष्टाचार, राजनीतिक अपराधीकरण एवं जाति-सम्प्रदाय के हिंसक आग्रहों पर इंडिया गठबंधन में कोई बहस नहीं है, कोई आदर्श राष्ट्र निर्माण की दृष्टि एवं दिशा नहीं है। राजनीति में लगे लोगों में जब इन मसलों की गहराई तक जाने का धैर्य और गंभीरता चुक जाए, तो उनके मंच के संवाद पहले निम्न दर्जे तक गिरते हैं और फिर कीचड़ को ही संवाद का विकल्प मान लिया जाता है। इन दिनों यही हो रहा है। भ्रष्टाचार के लिए मोदी सरकार जो कार्रवाइयाँ कर रही हैं, वह सराहनीय है। भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुके ऐसे नेताओं की कमी नहीं है, जो यह मानते हैं कि सरकार उनकी है और वे कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह की भ्रामक सोच भारतीय राजनीति का पतन कर रही है। इसकी शुचिता और पारदर्शिता को धूमिल कर रही है। पहले राजनीति का अर्थ लोगों की सेवा करना होता था, लेकिन बाद में यह अपने लोगों की सेवा का माध्यम समझी जाने लगी। बिहार, बंगाल, दिल्ली और झारखंड जैसे राज्य तो इसमें सबसे ऊपर दिखते हैं। झारखंड में ही अभी जो घटनाक्रम हुआ है, क्या उससे यह धारणा नहीं बनती कि हेमंत सोरेन ने जरूर कुछ ऐसे कार्य किए हैं कि पहले उन्हें ईडी से भागना पड़ा और जब उन पर दबिश बढ़ी, तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर ईडी अधिकारियों के हाथों गिरफ्तार होना पड़ा।

बिहार का हाल भी झारखण्ड से अलग नहीं है। वहां पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का भ्रष्टाचार लगातार खबरों में रहा है, वे भी सजा भुगत चुके हैं। उनके पुत्र तेजस्वी यादव व अन्य परिजन पर भी जमीन घोटाले के आरोप हैं। कहा जाता है कि जब ईडी ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछे, तो वह भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने घोटाले के वक्त खुद के नाबालिग होने की बात कही। जब ईडी अधिकारियों ने पूछा कि करोड़ों की कंपनी कैसे बनाई, तो उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी न होने की बात कही। जबकि लालू यादव के पास इतनी संपत्ति कैसे जमा हुई, यह कोई छिपा रहस्य नहीं है। इसलिए यह कयास भी गलत नहीं है कि देर-सबेर तेजस्वी यादव भी अपने पिता की तरह जेल में दिख सकते हैं। कुछ इसी तरह की कहानी देश के अन्य राज्यों में भी है, जहां मुख्यमंत्री और बड़े नेता ईडी के निशाने पर हैं, इसलिए मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हम और भी कई नेताओं को कालकोठरी में देख सकते हैं।

बात केवल आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय जनता दल, की ही नहीं है, भ्रष्टाचार जहां भी हो, उसकी खिलाफ बिना किसी पक्षपात के कार्रवाई की जानी चाहिए। भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है, नया भारत एवं सशक्त भारत को निर्मित करने के लिये तत्पर है तो उसकी पार्टी के भीतर भी यदि भ्रष्टाचार है तो उसकी सफाई ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भ्झी दल के नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का बुगल बजाय हुए हैं तो यह आजादी के अमृत महोत्सव मनाने की सार्थक पहल है, जिसके माध्यम से वे भारत के विलक्षण और ऐतिहासिक प्रधानमंत्री माने जाएंगे। राजनीतिज्ञों की साख गिरेगी, तो राजनीति की साख बचाना भी आसान नहीं होगा। हमारे पास राजनीति ही समाज की बेहतरी का भरोसेमंद रास्ता है और इसकी साख गिराने वाले कारणों में अपराधीकरण और भ्रष्टचार के बाद तीसरा नंबर इस कीचड़ उछाल राजनीति का भी है, जिसमें गलत को गलत नहीं माना जाता। ये तीनों ही राजनीति के औजार नहीं है, इसलिए राजनीति को तबाही की ओर ले जाते हैं। अपराधीकरण और भ्रष्टाचार का मसला काफी गहरा है और इससे खिलाफ लड़ाई के लिए काफी वक्त और ऊर्जा की जरूरत है, लेकिन कीचड़ उछाल से परहेज करके और सार्थक बहस चलाकर देश की राजनीति का सुधार आंदोलन शुरू किया जा सकता है। राजनैतिक कर्म में अपना जीवन लगाने वालों से इतनी उम्मीद तो की ही जानी चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों को राजनीतिक रंग न दे। ऐसी ही उम्मीदभरी एवं स्वच्छ राजनीति से भारत का लोकतंत्र समृद्ध हो सकेगा।

नाम, एड्रेस सुधार के लिए लग रही कलेक्टोरेट में छात्रों की भीड़

एसटी-एससी वर्ग के छात्र दिन भर डटे रहते हैं दूसरी मंजिल पर

इंदौर। मार्कशीट और अन्य दस्तावेजों में नाम एड्रेस सहित अन्य महत्वपूर्ण डाटा सुधारने को एससी एसटी वर्ग के छात्र परेशान हो रहे हैं। कलेक्ट्रेट की दूसरी मंजिल पर आदिम जाति विकास विभाग के बरामदे में बड़ी संख्या में छात्र जमा हो रहे हैं। अभी यहां अपने दस्तावेजों में डाटा सुधारने के लिए दिन भर लगे भी रहते हैं। अधिकारी भी जितना जल्दी हो रहा है उनके दस्तावेजों में सुधार कर उनकी मदद कर रहे हैं। यह सुधार भी छात्रों को अपनी ही पूर्व में की गई गलतियों के कारण करवाना पड़ रहा है।

जानकारी अनुसार कलेक्टोरेट के दूसरी मंजिल स्थित आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यालय के बाहर इन दिनों भारी भीड़ दिखाई दे रही है। यह भीड़ उन छात्रों की है जिन्होंने अपने दस्तावेजों में फॉर्म भरते समय ही जल्दबाजी में गलतियां कर दी है। अब जब यह सामने आई है तो उन्हें दुरुस्त करवा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार जब परीक्षा फॉर्म या एडमिशन फॉर्म छात्रों द्वारा भरा जाता है तो वह जल्दबाजी में ध्यान न देते हुए जानकारी भर देते हैं। कई बार वे जल्दबाजी में गलत जानकारी भी प्रविष्ट कर देते हैं, जिनके कारण निकट भविष्य में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब समय रहते ही जब इन्हें पता चल गया है तो यह उन गलतियों को दुरुस्त करवाने में लगे हैं। इनमें कुछ छात्र तो ऐसे भी सामने आए हैं जिन्होंने अपने नाम तक की स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी है। उसे भी सही किया जा रहा है।

स्कॉलरशिप के लिए भी आए कुछ छात्र

कुछ छात्रों ने बताया कि वह ऐसी वर्ग से संबंधित है। उनके कॉलेज से उन्हें लंबे समय से स्कॉलरशिप प्रदान नहीं की गई है। जब इस बारे में कॉलेज प्रबंधन से बातचीत की तो वहां से पता चला कि फॉर्म में कुछ गड़बड़ है या अन्य कोई ऐसा कारण है जिसके लिए कॉलेज से सुधार नहीं किया जा सकता इसलिए यह सुधार करवाने आए हैं प्रोग्राम अब हमें उम्मीद है कि यहां से जानकारी सही होने के बाद अकाउंट में स्कॉलरशिप जल्द ही आ जाएगी।

लोकसभा चुनाव के लिए कलेक्टोरेट में ईवीएम का प्रदर्शन

विधानसभा क्षेत्रवार लोगों को दे रहे वोट देने की जानकारी

इंदौर। कलेक्टर ऑफिस में लोकसभा चुनाव की सुविधा शुरू हो गई है। इसके पहले चरण में मतदान अधिकारियों द्वारा ईवीएम का प्रदर्शन कलेक्टोरेट में किया जा रहा है। कलेक्टर ऑफिस की तल मंजिल में अलग-अलग पोलिंग अधिकारी विधानसभा क्षेत्र वार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से वोट डालने की प्रक्रिया लोगों को समझ रहे हैं। यहां अलग-अलग विधानसभा वार ईवीएम प्रदर्शन टेबलें लगाई गई हैं, जिन पर उपलब्ध पीठासीन अधिकारी लोगों को ईवीएम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मतदान अधिकारियों ने बताया कि लोगों के मन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जो भाई और सन से रहता है उसे दूर करने के लिए यह प्रदर्शन केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही यहां लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट डालने की प्रक्रिया भी समझाइए जा रही है। इसके लिए प्रयोग मतदान भी करवाया जा रहा है, जिससे व्यक्ति आसानी से वोट डाल सके। इस प्रक्रिया को समझने के बाद मतदान के समय मतदाताओं को वोट डालने में आसानी होगी। साथ ही पोलिंग टीम और मतदाताओं का समय भी बचेगा। इससे मतदान केदो पर अनावश्यक भीड़ नहीं होगी। यहां जो भी आवेदक विभिन्न कामों से आते हैं उन्हें ईवीएम से मतदान की प्रक्रिया समझाइए जा रही है। जो भी व्यक्ति यहां प्रयोग मतदान करता है उसका नाम पता मोबाइल नंबर संबंधी जानकारी एक रजिस्टर में भी दर्ज की जा रही है ताकि रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सके ।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा क्रिस्टल आईटी पार्क में आईटी मिलन समारोह का आयोजन

सर्वे भवंतु सुखिनः मात्र नारा नहीं, भारत का चिंतन है-विनय दीक्षित

इंदौर। इंदौर। राष्टीय स्वयं संघ की सबको साथ लेकर चलने की परंपरा ही देश में लोगों को जोड़ रही है। आज पूरा समाज संघ के साथ जुड़ रहा है। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवंतु सुखिनः आदि यह केवल नारे नहीं हैं, भारत का चिंतन है। देश जब अपनी स्वतंत्रता के सौवें वर्ष में प्रवेश करेगा तब जैसा हम अपना देश देखना चाहते हैं, हमें उसी हिसाब से चिंतन शुरू कर देना चाहिए। यह बात राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मालवा प्रांत के प्रचार प्रमुख विनय जी दीक्षित ने संघ द्वारा क्रिस्टल आईटी पार्क में आरएसएस के प्रथम आईटी मिलान समारोह को सम्बोधित करते हुए कही। उन्होंने संघ के आईटी प्रोफेशनल्स से आवाहन किया कि वो इस बात का संकल्प लें कि आधुनिक रूप से राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आइडियल आई.टी. टेक्नो प्रा. लि. कंपनी के सीईओ पवन राठौर ने कहा कि इस आईटी मिलन समारोह के माध्यम से आईटी के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोग समाज एवं देश हित में कार्य करने के लिए और प्रेरित होंगे।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर के आईटी प्रोफेशनल्स गणवेश धारण कर दंड योग, व्यायाम योग, आसन, समता प्रयोग में सामूहिक रूप से भाग लिया। इसके पश्चात संघ द्वारा प्रस्तावना एवं प्रतिवेदना प्रस्तुत किया गया जिसमें बताया गया कि संघ की यह शाखा किस तरह सरकारी योजनाओं को मलिन बस्तियों तक पहुंचाने, जरूरतमंदों को लाभ दिलाने, आइटी विद्यार्थियों को इंटर्नशिप करवाने आदि कार्य करती है। इस आईटी मिलन समारोह में बड़ी संख्या में आइटी कंपनियों के कर्मचारी, निदेशक, सीईओ आदि उपस्थित हुए।

बिजली कंपनी के एमडी ने किया बिचौली क्षेत्र के ग्रिड का निरीक्षण

इंदौर। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) श्री अमित तोमर ने मंगलवार को इंदौर बायपास के करीब बिचौली क्षेत्र की पांच कॉलोनियों एवं तीन गांवों की बिजली आपूर्ति के लिए आरडीएसएस योजना में बनाए बड़ियाकीमा 33/11 केवी के नए ग्रिड का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रिड का रजिस्टर भी बारीकी से देखा। ग्रिड के रजिस्टर में ट्रिपिंग का स्तर अवलोकन करने पर यह सामान्य पाया गया। एमडी श्री तोमर के दौरे के दौरान मुख्य अभियंता एवं आरडीएसएस योजना प्रभारी एसएल करवाड़िया, इंदौर ग्रामीण वृत्त के अधीक्षण यंत्री डॉ. डीएन शर्मा आदि मौजूद थे। उन्होंने ग्रिड निर्माण में अथक परिश्रम कर समय पर कार्यपूर्ण कराने वाले इंजीनियर ज्ञानेंद्र गौड़ एवं अभिषेक द्विवेदी से भी चर्चा की। कार्यपालन यंत्री अभिषेक रंजन ने बताया कि ग्रिड से पांच कॉलोनियों एवं बड़िया कीमा समेत तीन गांवों के साढ़े चार हजार उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता के साथ बिजली मिलना प्रारंभ हो गई हैं।

माता गुजरी कॉलेज के छात्र इंटर्नशिप के लिए पहुंचे अहिल्या लाइब्रेरी

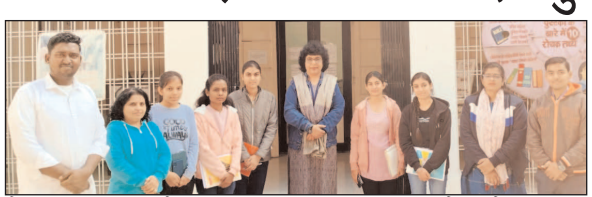

इंदौर। शासकीय देवी अहिल्या लाइब्रेरी में लगातार छात्रों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए लाइब्रेरी द्वारा विभिन्न प्रकार के अभियान भी चलाए जा रहे हैं ताकि छात्रों का झुकाव पुस्तकों की ओर हो सके। इसके तहत माता गुजरी कॉलेज के छात्र इंटर्नशिप के लिए लाइब्रेरी पहुंचे और उन्होंने जानकारियां प्राप्त की। मुख्य लाइब्रेरियन लिली

डावर ने बताया कि यहां छात्र भ्रमण करने आते हैं, आजीवन सदस्यता लेते हैं। पाठक कक्ष, विशेष अध्ययन कक्ष में प्रतिदिन अध्ययन भी करते हैं। इसी क्रम में माता गुजरी कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के छात्र इंटर्नशिप करने पुस्तकालय पहुंचे। सभी ने यहां भ्रमण करवाकर पुस्तकों के प्राप्ति स्थान, पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों का क्लासिफिकेशन, पुस्तकों का आदान-प्रदान आदि की जानकारी ली। इस दौरान मेघना चार्ल्स, पूर्णिमा पांचाल, रागिनी गौड़, रत्नेश देवलासे, अखिलेश आसीरवाला, रोहित खेर और सौरभ सिरसाट भी मौजूद रहे।

भाजपा दिल्ली दरबार से तय करेगी राज्यसभा प्रत्याशी

पवैया, जटिया, लालसिंह, अरविंद भदौरिया और रंजना बघेल प्रमुख दावेदार

भोपाल। *लोकसभा चुनाव से पहले मप्र की पांच राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। भाजपा के पाले में चार और कांग्रेस को एक सीट मिलेगी। भाजपा की चार सीटों पर दिल्ली दरबार से प्रत्याशी तय होंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार जातीय समीकरणों को साधने के लिए आलाकमान इस बार मप्र के तीन या फिर सभी चार नेताओं को राज्य सभा भेज सकती है। वर्तमान में जयभान सिंह पवैया, सत्यनारायण जटिया, लालसिंह आर्य, अरविंद भदौरिया और रंजना बघेल प्रमुख दावेदार बताए जा रहे हैं।*

भाजपा सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के समीकरणों को देखते हुए आलाकमान राज्यसभा प्रत्याशियों का नाम तय करेगा। हालांकि सूत्रों का कहना है कि भाजपा आलाकमान मध्य प्रदेश को तीन सीटें दे सकती है। पार्टी एक अन्य सीट पर केंद्र से प्रत्याशी भेज सकती है। फिलहाल मध्य प्रदेश से भेजे गए धर्मेंद्र प्रधान और डा. एल मुरुगन का कार्यकाल दो अप्रैल को समाप्त हो रहा है, इन दोनों ही नेताओं को पार्टी लोकसभा चुनाव लड़वाने की तैयारी में है। बचे दो राज्य सभा सदस्य मध्य प्रदेश से हैं। इनमें अजय प्रताप सिंह और कैलाश सोनी का भी कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। मप्र में क्षत्रिय वर्ग से सांसद रहे नरेंद्र सिंह तोमर और राकेश सिंह दोनों को ही केंद्रीय राजनीति से प्रदेश की सियासत में भेज दिए गए हैं। अरविंद भदौरिया तथा रामपाल सिंह राजपूत विधानसभा चुनाव हार गए हैं, ऐसे में पार्टी किसी बड़े क्षत्रिय चेहरे पर दांव लगा सकती है या कोई नया क्षत्रिय चेहरा ला सकती है। राज्यसभा चुनाव के लिए 8 फरवरी से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 15 फरवरी तक नामांकन स्वीकार किए जाएंगे। नाम 20 फरवरी तक वापस लिए जा सकेंगे। आवश्यकता होने पर मतदान सुबह 9 से चार बजे तक कराया जाएगा। पांच बजे से मतगणना होगी और फिर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

एक सदस्य के लिए 39 मतों की आवश्यकता

गौरतलब है कि आठ फरवरी से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 15 फरवरी तक नामांकन स्वीकार किए जाएंगे। नाम 20 फरवरी तक वापस लिए जा सकेंगे। आवश्यकता होने पर मतदान सुबह नौ से चार बजे तक कराया जाएगा। पांच बजे से मतगणना होगी और फिर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश से रिक्त होने वाली पांच सीटों में से चार भाजपा और एक कांग्रेस के पास है। 230 सदस्यीय विधानसभा में दलीय स्थिति के अनुसार चार सीटें फिर भाजपा को मिलनी तय है। पार्टी के 163 विधायक हैं। एक सदस्य के निर्वाचन के लिए 39 मतों की आवश्यकता होगी। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर भाजपा के चार सदस्य चुनकर आएंगे। वहीं, कांग्रेस एक सदस्य निर्वाचित कराने की स्थिति है। कांग्रेस के विधायक की संख्या 66 है, जबकि एक सदस्य भारत आदिवासी पार्टी से है।

जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर जोर

भाजपा लोकसभा चुनाव के समीकरण साधने के लिए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधने के लिए राज्यसभा प्रत्याशियों का नाम तय करेगी। भाजपा नेताओं के अनुसार पार्टी चाहती है कि एक- एक एससी-एसटी और एक सामान्य वर्ग से प्रत्याशी बनाया जाए। चूंकि, नरेंद्र सिंह तोमर और राकेश सिंह दोनों ही केंद्रीय राजनीति से प्रदेश की सियासत में भेज दिए गए हैं और अरविंद भदौरिया विधानसभा चुनाव हार गए हैं, ऐसे में पार्टी किसी बड़े क्षत्रिय चेहरे पर दांव लगा सकती है या कोई नया क्षत्रिय चेहरा ला सकती है। ग्वालियर-चंबल में केवल जयभान सिंह पवैया का ही ऐसा चेहरा है। वहीं, अनुसूचित जाति वर्ग से पार्टी और संघ सत्यनारायण जटिया को एक अवसर देना चाहती है। जटिया भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और इन दिनों संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं। पहले वे लंबे समय तक उज्जैन से सांसद रहे और अटल सरकार में मंत्री भी रहे। विकल्प के रूप में प्रदेश संगठन ने लालसिंह आर्य का नाम भी रखा है। अनुसूचित जनजाति वर्ग से रंजना बघेल को भी पार्टी ने लोकसभा या राज्यसभा मं भेजने का आश्वासन दिया था।

भाजपा में जा सकते हैं दरबार और पटेल

भोपाल। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस व अन्य पार्टियों के नेताओं से बात कर भाजपा की सदस्यता दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इंदौर में भी कांग्रेस के बड़े नाम रहे पूर्व विधायक अंतरसिंह दरबार और मोतीसिंह पटेल को लेकर मंथन चल रहा है। हालांकि दरबार को लेकर विधायक व कुछ स्थानीय नेताओं की आपत्ति है।

लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी चाहती है कि कांग्रेस के नाराज नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई जाए। इसके चलते इंदौर में भी कई नामों पर भाजपा संगठन में मंथन चल रहा है। बड़े नामों में महू के पूर्व विधायक दरबार प्रमुख हैं, जो विधानसभा का चुनाव निर्दलीय लड़े थे और 62 हजार वोट लेकर आए। उनके साथ चार जिला पंचायत सदस्य हैं तो जनपद सदस्यों व सरपंचों की संख्या भी अच्छी है। इसके अलावा राजपूत समाज में पैठ है।

हालांकि दरबार के भाजपा में आने की भनक लगने पर विधायक उषा ठाकुर और कुछ पदाधिकारियों ने आपत्ति दर्ज कराई कि इससे भाजपा के पुराने राजपूत नेताओं की राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा। वे सहकारिता के क्षेत्र में भी दखल रखते हैं तो पार्टी में आने का उन्हें कभी लाभ भी दिया जाएगा। ऐसे में सहकारिता की राजनीति करने वाले अन्य नेताओं का नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर, इंदौर दुग्ध संघ के अध्यक्ष मोतीसिंह पटेल भी भाजपा की सूची में मजबूत नाम है। पार्टी के पास कलोता समाज का मजबूत नेता नहीं है। उनके आने से ये कमी दूर हो जाएगी। विधायक मनोज पटेल से भी उनके संबंध अच्छे हैं। दोनों ही नेताओं को इसका फायदा हो सकता है।

अपनी टीम बनाने में जुटे मोहन...

भरोसेमंद अफसरों की कर रहे हैं नियुक्तियां

मंत्रियों को दिलवाए प्रशिक्षण की प्रशंसा प्रधानमंत्री ने भी की, मुख्यमंत्री सचिवालय को भी किया मजबूत, सोच-समझकर किए जा रहे हैं महत्वपूर्ण तबादले

भोपाल। मुख्यमंत्री के रूप में डॉ. मोहन यादव ने कम समय में ही अपनी छाप छोड़ी। वहीं उन्होंने सख्त निर्णय भी लिए। दूसरी तरफ गुड गवर्नेंस के लिए योग्य अफसरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा रही है और वे अपनी टीम बनाने में भी जुटे हैं। यही कारण है कि सोच-समझकर महत्वपूर्ण पदों पर तबादले किए जा रहे हैं। यहां तक कि मंत्रियों को भी

उन्होंने सुशासन का प्रशिक्षण अभी दिलवाया, जिसकी सराहना कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी की। जब मुख्यमंत्री उनसे मिले और अन्य योजनाओं के साथ लीडरशिप समिट के दो दिवसीय आयोजन की जानकारी भी उन्हें दी। इतना ही नहीं उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय का कायाकल्प भी शुरू किया।

शुरुआत में भले ही अधिकांश लोगों को यह लगा हो कि केन्द्रीय नेतृत्व ने वरिष्ठों को नजरअंदाज कर कनिष्ठ को मुखिया पद सौंप दिया और उन्हें काम करने में परेशानी आएगी। मगर एक-डेढ़ महीने के अपने अल्प कार्यकाल में ही डॉ. मोहन यादव ने इस तरह की अटकलों को खारिज कर दिया और गड़बड़ी पाए जाने पर तुरंत नौकरशाहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, तो दूसरी तरफ तबादलों के मामले में भी सोच-समझकर निर्णय लिए जा रहे हैं। इंदौर कलेक्टर के बाद पुलिस कमीश्नर के रूप में भी उन्होंने इसी तरह की नियुक्ति करवाई। जिन नौकरशाहों की कार्य प्रणाली को वे पहले से जानते हैं उन्हें अब बेहतर अवसर दिए जा रहे हैं। प्रमुख सचिव राघवेन्द्र सिंह का चयन भी खरा साबित हुआ, जिन्होंने चंद दिनों में ही प्रदेश सरकार को कई मोर्चों पर सफलता दिलवाई और सचिवालय में भी आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों के अलावा अच्छा प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को ही नियुक्त किया गया। जनसम्पर्क आयुक्त के रूप में जहां संदीप यादव को लाया गया, तो अभी जो तबादला सूची दो दिन पहले आई उसमें भरत यादव, अविनाश लवानिया, अंशुल गुप्ता, चंद्रशेखर वालिंबे और अदिति गर्ग को भी मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ किया गया। ये सभी अधिकारी बेहतर कार्य क्षमता के साथ नए विजन से जुड़े रहे हैं। इतना ही नहीं, मंत्रियों के लिए भी प्रशिक्षण रखवाया, जिसकी प्रशंसा मोदी जी ने भी की। कुल मिलाकर डॉ. मोहन यादव अपनी योग्य टीम बनाने में जुटे हैं, ताकि गुड गवर्नेंस का एक बेहतर मॉडल मध्यप्रदेश में खड़ा किया जा सके।

22 बाद भी लागू नहीं हुआ कंपाउंडिंग और टीडीआर

भोपाल । प्रदेश के नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 19 जनवरी को निर्देश दिया था कि अवैध निर्माण को वैध करने के लिए कंपाउंडिंग की सीमा को 30 प्रतिशत तक बढ़ाने और ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) लागू किया जाए। इसके लिए 15 जनवरी तक का समय सीमा तय की गई थी। लेकिन तकरीबन 22 दिन बाद भी प्रदेश के नगरीय निकायों के साथ ही इनमें रहने वाले लोगों के फायदे के लिए फैसले अब तक अमल में नहीं आ पाए हैं। अनुमति के अतिरिक्त 30 फीसदी तक निर्माण को वैध करने की राहत नहीं मिल पाई है और न ही ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) लागू हो पाए हैं।

हाउसिंग फॉर ऑल में 100 करोड़ का गड़बड़झाला

भोपाल। *जहां एक तरफ केंद्र और प्रदेश सरकार हर गरीब के सिर पर छत देने का प्रयास कर रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ हितग्राही मकान के लिए मिलने वाली राशि को अन्यत्र खर्च कर रहे हैं। इस कारण प्रदेश में मकान के लिए पहली किश्त लेकर व्यक्तिगत कार्य और शौक पूरा करने वालों की संख्या 10,000 से अधिक हो गई है। यानी इन डिफॉल्टर हितग्राहियों ने हाउसिंग फॉर ऑल में 100 करोड़ का गड़बड़झाला कर दिया है।*

भारत सरकार ने भारतीयों को अपना घर बनाने में मदद करने के उद्देश्य से 2015 में हाउसिंग फॉर ऑल मिशन शुरू किया था। इस मिशन के तहत, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जाना जाता है, आप अपने घरेलू आय वर्ग और अन्य मानदंडों के आधार पर अपने होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अफसरों के मुताबिक कई नगरीय निकायों में हितग्राहियों ने पहली किश्त मकान बनाने की बजाय कहीं और खर्च कर दी। व्यक्तिगत कार्य और शौक पूरा करने में इसका उपयोग कर लिया। बताया जा रहा है डिफॉल्टर हितग्राहियों की संख्या दस हजार से अधिक है। ऐसे में प्रति हितग्राही एक लाख के हिसाब से यह राशि 100 करोड़ रुपए के पार पहुंच जाती है। हालांकि कमिश्नर नगरीय प्रशासन भरत यादव का कहना है कि यह नहीं कह सकते हैं कि राशि खर्च कर दी। इसके लिए एक-एक प्रकरण देखना होगा। यह सही है कि कई लोगों ने मकानों का निर्माण शुरू नही किया है। कुछ को पट्टे नहीं मिले, कुछ लोग नहीं मिल रहे जैसे कारण हो सकते हैं। कलेक्टर सूची का अनुमोदन करते हैं। ऐसे में कलेक्टरों को लिखा है कि मकानों का निर्माण शुरू कराएं या फिर संबंधित हितग्राही से वसूली करें।

कहीं और खर्च कर दी

गौरतलब है कि हाउसिंग फॉर ऑल या पीएमएवाय योजना के चार घटक है। पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से रीडेवलपमेंट और दूसरा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है। फिर क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) और आखिरी बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुल हाउस कंस्ट्रक्शन (बीएलसी) है। बीएलसी में कमजोर आय वर्ग यानि ईडब्ल्यूएस तबके के लोगों को मकान निर्माण या इसके विस्तार के लिए 2.50 लाख रुपए की राशि केंद्र व राज्य की ओर से दी जाती है। बीएसली घटक में मकान का निर्माण शुरू करने के लिए पहली किश्त के तौर पर एक लाख रुपए तक दिए जाते हैं। फिर मकान की प्रगति के आधार पर बाकी राशि जारी की जाती है। इसके लिए उनकी जियो टैगिंग की जाती है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अफसरों के मुताबिक कई नगरीय निकायों में हितग्राहियों ने पहली किश्त मकान बनाने की बजाय कहीं और खर्च कर दी। व्यक्तिगत कार्य और शौक पूरा करने में इसका उपयोग कर लिया। बताया जा रहा है डिफॉल्टर हितग्राहियों की संख्या दस हजार से अधिक है। ऐसे में प्रति हितग्राही एक लाख के हिसाब से यह राशि 100 करोड़ रुपए के पार पहुंच जाती है।

अधिकारियों की लापरवाही भी

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को छत मुहैया कराने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तीन माह के भीतर चयनित लाभार्थियों का आवास पूरा कराने का लक्ष्य दिया गया था लेकिन पिछले पांच सालों के आंकड़ों को देखा जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना वाले घर अधूरे पड़े हैं जिनको समय रहते ही पूरा कर दिया जाना चाहिए था। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता के चलते अभी भी ढेर सारे आवास ऐसे हैं जो अधूरे पड़े हैं। वहीं हजारों हितग्राही तो ऐसे भी हैं जिन्होंने पहली किश्त लेने के बाद दूसरी किश्त के लिए आवेदन ही नहीं किया है। जब इसकी पड़ताल की गई तो यह तथ्य सामने आया कि उन्होंने पहली किश्त को मकान बनाने की जगह दूसरी जगह उपयोग कर लिया है। अब उनसे यह राशि वसूल करने की तैयारी की जा रही है।

अब वसूली में लगा विभाग

दरअसल, मकान बनाने के लिए मिले पैसे हजारों हितग्राहियों ने कहीं और खर्च कर दिए। किसी ने बाइक खरीद ली तो किसी ने शादी में उड़ा दिए। अब इनको तलाशने और फिर वसूली करने के लिए अफसर परेशान हो रहे हैं। ऐसे में नगरीय प्रशासन संचालनालय ने कलेक्टरों को डिफॉल्टर्स से रिकवरी के लिए लिखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में मप्र के लिए 11 लाख से अधिक आवासहीन चिन्हांकित किए गए थे। मौजूदा स्थिति में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी, एचआईजी टाइप के लगभग नौ लाख मकान बन चुके हैं। इसमें से अधिकांश हितग्राहियों को आवंटित हो चुके हैं। दो लाख से अधिक मकान अभी नहीं बन पाए हैं। भोपाल के लिए योजना का एक्शन प्लान वर्ष 2015 में मंजूर हुआ था। इसमें पीपीपी से रीडेवलपमेंट के जरिए 62,383 और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में 63,646 मकान मंजूर हुए थे। सीएलएसएस घटक में 13383 और बीएलसी में भी इतने ही आवासो का निर्माण प्रस्तावित था। इस तरह कुल 1, 52, 795 मकानों के निर्माण का टारगेट था। भोपाल में पीपीपी और बीएलसी घटक में एक भी आवास का निर्माण नही किया गया। ऐसे में राजधानी में बीएलसी घटक में कोई भी डिफॉल्टर हितग्राही नहीं है। वहीं कई निगमों में पहली किश्त लेकर कही और खर्च कर देने वालों की संख्या सैकडों में है।

विद्यार्थियों को सम्राट विक्रमादित्य की न्यायप्रियता, दानशीलता, पुरुषार्थ, पराक्रम और सुशासन की प्रेरणा मिलेगी : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

ग्राम बगवाड़ा (बुधनी), सीहोर में विद्याभारती मध्यप्रांत के सम्राट विक्रमादित्य सैनिक स्कूल का शिलान्यास

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीहोर जिले की बुधनी तहसील के ग्राम बगवाड़ा में विद्याभारती मध्यप्रांत द्वारा प्रारंभ किये जा रहे सम्राट विक्रमादित्य सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर बनने वाले सैनिक स्कूल में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्राट विक्रमादित्य की न्यायप्रियता, दानशीलता, पुरुषार्थ, पराक्रम और सुशासन की शिक्षा और प्रेरणा मिलेगी।

कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, स्वामी ईश्वरानंद महाराज (उत्तम स्वामी), आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री सुरेश सोनी, विजय कुमार सिन्हा, अशीष चौहान, श्री श्रीराम अरावकर ने भी संबोधित किया। राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, सांसद श्री रमाकांत भार्गव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री सीताशरण शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विद्या भारती संस्थान द्वारा इस सैनिक स्कूल के माध्यम से विद्यार्थियों में संस्कार और राष्ट्रनिर्माण की भावना को विकसित करने का काम किया जायेगा। नई शिक्षा नीति के निर्माण में विद्या भारती संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रदेश में जहाँ भी सैनिक स्कूल शुरू किए जाएंगे वहां प्रदेश सरकार पूरी मदद करेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विद्या भारती मध्यभारत प्रांत द्वारा यहां सम्राट विक्रमादित्य सैनिक स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। स्कूल परिसर में आधुनिक शिक्षा की सुविधा, सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं उपलब्ध रहेंगीं।

नर्मदा नदी एवं नेशनल हाईवे-46 के पास वन एवं पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे इस स्थान पर भारतीय सेना के कौशल और संस्कारों के साथ शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस भवन की नींव नवग्रह विधान, वास्तु पुरुष एवं अन्य सांस्कृतिक मूल्यों पर रखी जा रही है।

जिला अस्पताल एवं सिविल अस्पतालों को और सशक्त बनाया जाएगा-उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

मेडिकल कॉलेज ग्वालियर की 9वीं सामान्य परिषद की बैठक में शामिल हुए

भोपाल। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा है कि ग्वालियर में जिला अस्पताल मुरार, सिविल अस्पताल हजीरा के साथ ही डबरा एवं भितरवार के अस्पतालों का उन्नयन किया जाए, जिससे एक हजार बिस्तर अस्पताल में आने वाले मरीजों को प्रारंभिक स्तर पर ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें मिल सकें। उप मुख्यमंत्री ने गजराराजा चिकित्सा समूह परिसर में सीवर समस्या के निदान के लिये शीघ्र प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल की अध्यक्षता में ग्वालियर मेडिकल कॉलेज की 9वीं सामान्य परिषद की बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने ग्वालियर के एक हजार बिस्तर अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और कमलाराजा अस्पताल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

रिक्त पड़े पदों की पूर्ति की जाए

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि अस्पतालों में रिक्त पड़े पदों की पूर्ति के लिये शीघ्रता से कार्रवाई की जाए। नर्स एवं वार्ड ब्वॉय के जितने भी पद हैं उन्हें प्राथमिकता से भरा जाए, जिससे मरीजों की बेहतर देखभाल हो सके। अस्पतालों में बेहतर उपचार के लिए आवश्यक उपकरण एवं अन्य सुविधाओं के लिए सांसद निधि, विधायक निधि एवं सीएसआर मद से राशि और सहयोग प्राप्त करने के सार्थक प्रयास किए जाएँ। अस्पतालों में दवाओं की सतत आपूर्ति बनी रहनी चाहिए। अस्पतालों में लगभग 80 प्रतिशत दवायें उपलब्ध हो रही हैं, जो दवाएँ उपलब्ध नहीं हो रही हैं उन्हें प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र से क्रय किया जाए।

पेशेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर होगा गंभीरता से विचार

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि निजी चिकित्सालों की तरह शासकीय अस्पतालों में भी मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिये पेशेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लागू करने पर गंभीरता से विचार किया जायेगा। इसके लागू होने से अस्पताल में आने वाले मरीजों को तत्परता से स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध होंगीं। उपमुख्यमंत्री ने जनरेटर, लिफ्ट एवं अन्य उपकरणों के मेंटेनेंस की स्वीकृति प्रदान की और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल में चिकित्सकों के प्रमोशन एवं अन्य प्रकरणों के संबंध में शासन स्तर से शीघ्र निर्णय के लिये औपचारिकताओं की पूर्ति के निर्देश दिए।

बैठक में महापौर डॉ. शोभा सतीश सिकरवार, विधायक मोहन सिंह राठौर, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त तरूण पिथोड़े, संभागीय आयुक्त दीपक सिंह, डीन मेडिकल कॉलेज डॉ अक्षय निगम, अधीक्षक जेएएच डॉ आर एस धाकड़ उपस्थित थे।

BOLLYWOOD UPDATE

अनन्या पांडे ग्लैमर की दुनिया से जुड़ी हैं और इसलिए उनकी प्रेजेंस सोशल मीडिया पर होनी बेहद जरूरी है। लेकिन वास्तव में वह खुद सोशल मीडिया से दूरी बनाना चाहती हैं। हालांकि, वह ऐसा नहीं कर सकती हैं। उनकी इच्छा है कि वह अपने सोशल से सभी सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दें।

सोशल मीडिया से दूरी बनाना चाहती हैं अनन्या पांडे

मशहूर अभिनेता चंकी पांडे की लाडली बेटी अनन्या पांडे ने बेहद ही कम समय में बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अनन्या ने साल 2019 में आई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद, उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। उनकी लास्ट फिल्म खो गए हम कहां जब ओटीटी पर रिलीज हुई तो दर्शकों ने इसे भरपूर प्यार दिया।

अनन्या पांडे ग्लैमर की दुनिया से जुड़ी हैं और इसलिए उनकी प्रेजेंस सोशल मीडिया पर होनी बेहद जरूरी है। लेकिन वास्तव में वह खुद सोशल मीडिया से दूरी बनाना चाहती हैं। हालांकि, वह ऐसा नहीं कर सकती हैं। उनकी इच्छा है कि वह अपने सोशल से सभी सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दें। इसके पीछे उनकी एक खास वजह भी है। तो चलिए आज इस लेख में हम जानेंगे कि आखिरकार अनन्या पांडे क्यों अपने फोन से सभी सोशल मीडिया ऐप्स को हटाना चाहती हैं-

फोन को नहीं करती ऑफ

अनन्या पांडे सोशल मीडिया से होने वाले नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में अच्छी तरह समझती हैं। लेकिन वह चाहकर भी अपने फोन को महज पांच मिनट के लिए भी बंद नहीं कर सकतीं। ऐसे में सोशल मीडिया पर होने वाली नेगेटिव ट्रोलिंग कहीं ना कहीं उन्हें भी इफेक्ट करती है। भले ही अनन्या पांडे से अपने फोन से सोशल मीडिया ऐप्स को हटाया नहीं है, लेकिन अब वह सोशल मीडिया पर उतनी एक्टिव नहीं हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर कई पेजों को म्यूट करना, रिस्ट्रिक्ट करना और ब्लॉक करना शुरू कर दिया है, जो उन्हें किसी भी तरह से दुख पहुंचाते हैं या फिर बुरा फील करवाते हैं। अनन्या पांडे के लिए सोशल मीडिया बहुत ही टॉक्सिक और घुटन भरा हो गया था, इसलिए अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया को अलग तरह से हैंडल करना शुरू कर दिया है।

अकेले समय बिताना करती हैं पसंद

अनन्या पांडे को सोशल मीडिया और अपने आसपास के लोगों से दूर कुछ वक्त के लिए अकेले समय बिताना काफी अच्छा लगता है। दरअसल, वह लगातार लोगों, उनकी सलाह और विचारों से घिरी रहती है। ऐसे में उनके आसपास बहुत शोर होता है, इसलिए अकेले समय बिताना और अपनी आवाज सुनना ही उन्हें काफी शांत महसूस करवाता है।

शाहरुख की इस फिल्म के लिए सोनम ने दिया था ऑडिशन

शाहरुख खान ने परदे पर कई हीरोइन्स के साथ काम किया है। काजोल, माधुरी दीक्षित, अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण और अनुष्का शर्मा समेत कई ऐसी हीरोइन्स हैं, जिनकी परदे पर किंग खान के साथ एक से ज्यादा बार जोड़ी बनी है। लेकिन अभी भी कई एक्ट्रेस ऐसी हैं, जो बिग स्क्रीन पर शाहरुख के साथ अभी तक नजर नहीं आई हैं। इन्हीं में से एक एक्ट्रेस हैं सोनम कपूर। किंग खान के साथ सोनम अभी तक किसी फिल्म में नजर नहीं आई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सोनम ने अपने करियर की शुरुआत में ही शाहरुख की एक फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था। यह फिल्म तो सुपरहिट रही थी लेकिन इसमें सोनम की जगह किसी और एक्ट्रेस को शाहरुख के अपोजिट साइन किया गया था। आइये जानते हैं इस दिलचस्प किस्सा के बारे में-

फिल्म रब ने बना दी जोड़ी के लिए सोनम कपूर ने दिया था ऑडिशन

अनुष्का शर्मा ने शाहरुख खान के साथ फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म के लिए सोनम कपूर ने भी ऑडिशन दिया था। सोनम ने 2007 में संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उसके एक साल बाद फिल्म रब ने बना दी जोड़ी रिलीज हुई थी। आदित्य चोपड़ा, एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। सोनम की सांवरिया रिलीज होने के बाद भी उन्होंने इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था।

आंखों के हिसाब से चुनें आईशैडो

मेकअप भी सौंदर्य का एक अहम हिस्सा होता है। ऐसे में मेकअप चाहे आंखों का हो या चेहरे का उत्सुकता हर लड़की को होती है। बता दें कि अगर आप आंखों का मेकअप करने की सोच रहे हैं। अगर आप आंखों की सुंदरता को और बढ़ाना या निखारना निकालना चाहते हैं तो आप अपनी आंखों के कलर को ध्यान में रखते हुए आईशैडो का चुनाव कर सकते हैं। आज हम इस लेख के माध्यम से आपको बताएंगे कि आईशैडो का चुनाव करने का तरीका क्या है।

ग्रे आंखों के लिए

बहुत कम लोग होते हैं जिनकी आंखों का रंग ग्रे होता है।

ऐसे में जिन लोगों की आंखों का रंग ग्रे है वह बहुत सोच समझकर आईशैडो का चुनाव करें। ग्रे आंखों पर डार्क कलर्स ज्यादा अच्छे लगेंगे। इसके अलावा आप मिलते-जुलते कलर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं।

जिन लोगों की आंखों का कलर भूरा है

जिन लोगों की आंखों का रंग भूरा होता है उन पर हर कलर अच्छा लगता है। आप न्यूट्रल रंग का चयन करेंगे तो ज्यादा आकर्षित दिखेंगे।

इसके लिए आप सेलमन और ब्रोंज गोल्ड का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप और अच्छा लुक पाना चाहते हैं तो आप इन कलर्स के साथ ब्लैक शेड भी दे सकते हैं।

जिनकी आंखों का कलर हरा होता है

जिनकी आंखों का कलर हरा होता है वह खुद में ही बेहद आकर्षित होते हैं। उन्हें किसी भी शैड की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप आईशैडो का चुनाव करती हैं तो रात की पार्टी के लिए पर्पल कलर और दिन की पार्टी के लिए शिवरी ब्राउन ज्यादा अच्छा लगेगा।

जिनकी आंखों का कलर नीला

नीला कलर ठंडक का प्रतीक भी होता है। ऐसे में हल्के और न्यूट्रल रंग इन आंखों पर बहुत अच्छे लगते हैं।

लेकिन ध्यान रहे जिनकी आंखों का कलर नीला होता है वह डार्क और स्मोकी लुक से बचें क्योंकि इससे उनका लुक खराब हो सकता है।

काली आंखों के लिए

जिनकी आंखों का कलर काला होता है उन पर डार्क कलर ज्यादा अच्छे लगते हैं इसलिए आप जब भी आईशैडो को चुनाव करें तो वॉयलेट, डार्क ब्लू और चॉकलेटी रंग का चुनाव करें। इससे ना केवल आप सुंदर दिखेंगे बल्कि निखरी हुई भी दिखेंगी।

पुराने विचार की महिलाओं में आम धारणा रहती है कि दो प्राणियों का भोजन करना है, अतः ज्यादा खा लेती हैं। यह उचित नहीं है। खाना अधिक नहीं खाकर पौष्टिक तत्वों की भरमार वाला भोजन करना चाहिए।

गर्भवती महिला को चाहिए पौष्टिक भोजन

बच्चे का निर्माण, पोषण, उसका स्वास्थ्य व मां का स्वास्थ्य गर्भवती के भोजन पर सर्वाधिक निर्भर करता है, इसलिए यह एक गर्भवती के भोजन में अतिरिक्त बढ़ाए जाने वाले तत्व ये हैं: प्रोटीन, कैल्शियम, लोहा, विटामिन। इसलिए इन पौष्टिक यह उचित नहीं। इन सबों से गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंचता है। आवश्यक भोज्य तत्वों की कमी के साथ-साथ इनके प्रयोग से होने वाली बीमारियां भी घर कर लेती है। गर्भवती का भोजन पौष्टिक के साथ-साथ सुपाच्य भी होना चाहिये। महिलाओं को दूध, दही, पनीर से बने पदार्थों को प्रधानता देनी चाहिए। दूध, दही की जगह छाछ का प्रयोग भी किया जा सकता है क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में मौजूद रहता है जो बच्चों की हड्डियों व मां के दांतों की सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। फल भरपूर मात्रा में लें। फलों का तात्पर्य महंगे फलों से नहीं। मौसमी फल, जो कि सस्ते भी होते हैं, समान मात्रा में उपयोगी हैं।

गर्भवती को भोजन संबंधी इन मुख्य सावधानियों की जानकारी आवश्यक है...

-भोजन ताजा हो और स्वच्छता से पकाया गया हो।
-कब्ज न होने देना।
पर्याप्त पानी पीना।
-सब्जियों का सूप लेना।
-आहार में तली भुनी, मिर्च मसाले वाली चीजों का कम-से-कम प्रयोग।
-फल, दूध, दही का प्रयोग।
-न भूख से अधिक खाना, न भूखा रहना।
-भोजन चिंतारहित, शांत मनः स्थिति में करना।
-भोजन के पश्चात् कम से कम आधा घंटा विश्राम करना।
-प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, लौहयुक्त अतिरिक्त भोजन लेना
-बजट के अभाव में सस्ते पौष्टिक भोजन की जानकारी लेना।
-भोजन में पोषण की कमी होने पर डॉक्टर की राय से विटामिनों की गोलियां व टॉनिक लेना।
-यदि आप ये सावधानियां लें तो कोई कारण नहीं कि आप और आपका बच्चा स्वस्थ न हों क्योंकि उचित आहार ही स्वास्थ्य का आधार है।

बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय है जिसे हर महिला को जानना जरूरी है। पुराने विचार की महिलाओं में आम धारणा रहती है कि दो प्राणियों का भोजन करना है, अतः ज्यादा खा लेती हैं। यह उचित नहीं है।

खाना अधिक नहीं खाकर पौष्टिक तत्वों की भरमार वाला भोजन करना चाहिए।

तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए न कि अनाज और घी की।

कुछ महिलाओं की यह धारणा रहती है कि गर्भकाल में जो खाने की इच्छा हो, वह अवश्य खाना चाहिए। कभी खट्टा खाने की इच्छा होती है तो कभी खूब चरपरा। कभी खूब ठंडा पीने की इच्छा होती है तो कभी-खूब चाय या कॉफी। ये दोनों ही गलत हैं। कई महिलाएं तो मिट्टी तक खाती हैं।

सिंहस्थ घोटाले के बीजेपी सांसद गुमानसिंह डामोर के विरूद्ध एमपी, एमएलए कोर्ट में बयान दर्ज

इंदौर। एम.पी., एम.एल.ए. भ्रष्टाचार से संबंधित विशेष न्यायालय, इन्दौर के न्यायाधीश सुरेश यादव द्वारा धर्मेन्द्र शुक्ला द्वारा प्रस्तुत परिवाद में धर्मेन्द्र शुक्ला सहित गवाह राजेश जौहरी के बयान दर्ज किये गये। धर्मेन्द्र शुक्ला ने सिंहस्थ 2016 उज्जैन में किये गये भारी भ्रष्टाचार एवं घोटाला करके बी.जे.पी. के भ्रष्ट सांसद गुमानसिंह डामोर द्वारा लगभग दस करोड़ से अधिक रूपयों का जनधन को चूना लगाया, के विरूद्ध परिवाद एम.पी., एम.एल.ए. अदालत में भा.द.वि. की धारा 420, 120बी, 124 (क), 166, 167, 107, 200, 381, 406, 408, 468, 491 के तहत पेश किया है। प्रकरण 2016 सिंहस्थ मेला उज्जैन से संबंधित है, जिसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा मेला क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्र में पानी की टंकियाँ व उनके स्टैण्ड, हेण्डपम्प, कुऐं,

बोरिंग, पानी सप्लाई आदि का कार्य किया गया था, जो उस समय के मुख्य अभियंता गुमानसिंह डामोर द्वारा किया और करवाया गया था। कार्य का टेण्डर डामोर को पास करना था। डामोर ने अपने अधिकार का दुरूपयोग करते हुये नियम विरूद्ध कायदे कानून ताक पर रखकर एक अयोग्य ठेकेदार जुबेर खान को करोड़ों के कार्य का ठेका दे दिया तथा जुबेर खान द्वारा प्रस्तुत इन्दौर नगर पालिक निगम के फर्जी प्रमाण पत्र को भी स्वीकार कर जुबेर खान को ठेका दिया। इस प्रकार गुमानसिंह डामोर और जुबेर खान व अन्य लोगों ने मिलकर शासन को करोड़ों रूपयों का चूना लगाकर आपस में मिल-बांटकर जन-धन को धोखाधड़ी से अपने पद का दुरूपयोग करते हुये गंभीर हानि पहुंचाई। इस भ्रष्ट को सांसद बनाकर पार्टी ने भी उसके भ्रष्टाचार को सराहनीय कार्य माना है। प्रकरण अब आगामी कार्यवाही के लिए नियत किया गया है। प्रकरण में धर्मेन्द्र शुक्ला की ओर से पैरवी अभिभाषकगण हरीश शर्मा, जी.डी.आर्य, शम्मी कदम व संजय पाराशर द्वारा की जा रही है।

इंदौर के अजय अवस्थी केंद्र सरकार के पक्ष में पैरवी करने के लिए पैनल में शामिल

इंदौर। राष्ट्रपति द्रोपती मुर्मू ने केंद्र सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने वाले देश भर के अभिभाषकों की नियुक्ति कर दी है, जिसके पैनल में इंदौर के सुप्रीम कोर्ट के अभिभाषक अजय अवस्थी भी शामिल है। श्री अवस्थी ने जाने-माने दिग्गज वकील रहे श्री राम जेठमलानी व महेश जेठमलानी के सानिध्य में वकालत की है। श्री अवस्थी की । नियुक्ति पर मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट,विधायक रमेश मेंदोला,गोलू शुक्ला, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और अभिभाषक रूपाली मिश्रा चौबे, विकास पांडे, सुरभि सांखला, नेहा रावत, योगेश मिश्रा, पंकज मिश्रा, अर्पण शर्मा,रोहन वर्मा,केतन सोनी आदि ने बधाइयां दी है।

बेटी का पेपर और पिता की हो गई मौत, परिजनों ने दिलवाई परीक्षा

इंदौर। खाना खाकर टहलना के बाद आराम से सोए पचास वर्षीय व्यक्ति की घबराहट के बाद मौत हो गई। मामला पलासिया थाना क्षेत्र का है। पलासिया पुलिस के अनुसार विनोबा नगर निवासी रमेश उम्र पचास वर्ष पिता श्रीनाथ बोरासी रात में खाना खाकर टहलने निकले और आकर कुछ देर बाद सो गए । आधी रात के दरमियान घबराहट की शिकायत करने पर परिजन उन्हें अस्पताल ले गए । जहां डॉक्टरो ने मृत घोषित कर दिया । बताया जा रहा है कि मृतक की तीन बेटियां हैं और उनमें सबसे बड़ी बेटी कली का बारहवीं का पेपर होना है। बेटी कली पढ़ाई छोड़कर परिवार और अपनी दो बहनों कशिश ओर कनक को ढांढस बंधाती रही । दुखद हादसे के बाद कली भी 12 वीं का पेपर देने से इंकार कर रही थी लेकिन परिवार ने उसके हिम्मत दी और परिजन ने उसे छावनी स्कूल कै परीक्षा सेंटर पर पहुंचाया । पुताई का काम करने वाला मृतक रमेश करीब एक माह से कनाड़िया के एक बंगले पर चौकीदारी कर रहा था।

14 लाख रुपए लूट के आरोपी पुलिसकर्मी को किया बर्खास्त

इंदौर। खाकी को दागदार करने वाले 14 लाख की लूट मामले में आधा दर्जन से अधिक आरोपियों में शामिल दो पुलिसकर्मियों दीपक और योगेश सिंह को डीसीपी राजेश सिंह ने बर्खास्त करते हुए नौकरी से निकाल दिया है। उक्त दोनों पुलिसकर्मियों ने अन्य आरोपी साथियों के साथ मिलकर अहमदाबाद जा रही बस को चैकिंग के नाम पर रोककर ड्राइवर के पास बैग में रखे रुपए लूटकर आपस में बांट लिए थे । हालांकि मामले में सभी आरोपियों को गिरफतार किया जा चुका है और फिलहाल सभी आरोपी जेल में हैं। मामले में 23 दिसंबर की रात अंकित जैन निवासी स्कीम 51 ने अपने कर्मचारी भाविक के जरिए 14 लाख रुपए एक बैग पार्सल से अहमदाबाद के कन्हैयालाल पटेल के लिए भिजवाये थे । भाविक ने पार्सल पंजाब ट्रेवल्स की बस के चालक नरेंद्र तिवारी को दिया था । पार्सल नहीं पहुंचने पर अंकित जैन ने 25 दिसंबर को ड्राइवर नरेंद्र पर चंदन नगर थाने में केस दर्ज करवाया था । नरेंद्र ने पूछताछ में खुलासा किया था कि बस को चंदन नगर थाने के दो पुलिसकर्मी रास्ते में रूकवा रुपयों से भरा पार्सल लूट ले गए थे । मामला अफसरों तक पहुंचने के बाद थाने के पुलिसकर्मियों की पहचान परेड कराई गई । जिसमें सिपाही दीपक यादव और योगेशसिंह चौहान दोनों को ड्राइवर ने पहचान लिया था । इसके चलते डीसीपी जोन 4 राजेश सिंह के निर्देश पर दोनों पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर लूट में शामिल पंजाब ट्रेवल्स के ही एक अन्य ड्राइवर , उसके भाई व दोस्तों सहित आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार करते लूट के करीब सात लाख रुपए बरामद भी कर लिए थे ।

कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्यवाही

64 अवैध निर्माण किए गए ध्वस्त, करोड़ों रुपये मूल्य की बेशकीमती शासकीय जमीन हुई अतिक्रमण मुक्त

इन्दौर। इन्दौर जिले में शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण कर उस पर कब्जा करने तथा अवैध रूप से शासकीय ज़मीन बेचने वालों के विरूद्ध कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर जिला प्रशासन के अमले द्वारा बड़ी कार्यवाही की जा रही हैं। इसी के तहत आज जिला प्रशासन,नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध रूप से किए गए 64 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। इस कार्यवाही में 8 करोड़ 65 लाख रूपये मूल्य की बेशकीमती शासकीय ज़मीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई। एसडीएम श्री ओमनारायण बड़कुल ने बताया कि नूरानी कालोनी, खिजरा पार्क

तथा एयरपोर्ट की दीवार के पास लक्ष्मी नगर में जिला प्रशासन,नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस क्षेत्र में शासकीय सेवा भूमि, सड़क की भूमि एवं नजूल भूमि को भूमाफियाओं द्वारा बेच दिया गया था। जिस पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों/दुकानों/फेक्ट्रियों के अवैध निर्माण को तोड़ा गया ।

श्री बडकुल ने बताया कि ग्राम बांक में खसरा नम्बर - 44 मद सेवा भूमि (शासकीय) में बने कच्चे टीन शेड के 18 मकान को तोडकर ग्राम बांक की सेवा भूमि रकबा 0.253 हेक्टयर भूमि जिसकी कीमत (बाजार मुल्य) 1 करोड 70 लाख रूपये के लगभग है। ग्राम सिरपुर में खसरा नम्बर 96/1 रकबा 2.673 हेक्टेयर पर बने नवीन व निर्माणाधीन अवैध मकान, गोदामनुमा, टीनशेड की बाजार मूल्य लगभग चार करोड 80 लाख रूपये है। इसी प्रकार सर्वे नम्बर 101 शासकीय भूमि (मद सडक) पर अवैध 11 पक्का गोडाउन व टीन शेड व्यवसायिक स्तर की छोटी फेक्ट्री बने हुए थे, जिन्हें तोड़ा गया। शासकीय रास्ते की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया, जिसकी बाजार मूल्य लगभग 2 करोड 15 लाख रूपये है। इस प्रकार आज कुल 3.973 हेक्टयर भूमि पर स्थित कुल 64 अतिक्रमण से हटाए गए जिसकी कुल बाजार मूल्य कीमत 8 करोड़ 65 लाख रूपये लगभग है।

धार भोजशाला - हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को दिया नोटिस

इन्दौर। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मथुरा, ज्ञानवापी वाराणसी के बाद अब मध्यप्रदेश में धार जिले की भोजशाला मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने भी एएसआई को नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही धार स्थित भोजशाला का मुद्दा फिर से गरमाने लगा है। दरअसल, भोजशाला को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में हिंदू संगठन, हिंदू संघ फॉर जस्टिस ने भोजशाला परिसर पर कब्जा देने और नमाज बंद कराने की मांग की है। जिसपर इंदौर हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार और भोजशाला कमेटी को नोटिस जारी किया है। अब भारतीय पुरातत?व सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर आगे कार्रवाई की जावेगी।

प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी जयश्री जैन द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स 13, प्रेस कॉम्प्लेक्स ए.बी. रोड इंदौर से मुद्रित एवं 22, प्रेस काम्पलेक्स, प्रेस हाऊस, ए.बी. रोड इंदौर 452008 से प्रकाशित। प्रधान संपादक- डॉ. राजेश जैन, मो. 9425322301 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)